संख्या-13/2017-1104/58-2017-38/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2017**

विषयः- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एस0एल0एस0सी0 से वर्ष 2016-17 में अनुमोदित 30 नान एन0एच0एम0 जनपदों की औद्यानिक विकास परियोजना धनराशि रू0-1510.61 लाख के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में अवमुक्त धनराशि रू0-625.00 लाख के व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-42-43/बजट-आर0के0वी0वाई0/2017-18, दिनांक 04.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-1465/12-3-2016-100(46)/2008, दिनांक 17.11.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना ''30 नान एन0एच0एम0 जनपदों की औद्यानिक विकास योजना'' के सापेक्ष प्रस्तावित कार्यक्रमों के वर्ष 2017-18 में क्रियान्वयन हेतु कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-428/12-3-2017/100(37)/2017, दिनांक 27.04.2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 625.00 लाख (रूपये छः करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2017 में उल्लिखित शर्तो एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

योजना का नाम	लेखाशीर्षक/मानक मद	कृषि अनुभाग-3 द्वारा अवमुक्त धनराशि
30नान एन0एच0एम0 जनपदों में औद्यानिक विकास परियोजना	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म- 800-अन्य व्यय- 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें 27-सब्सिडी	625.00
	योग	**625.00**

(रूपये छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(1) कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2017 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। पहली किश्त का आहरण अभी किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त दूसरी किश्त का आहरण किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में पुर्नरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम **Net** पर रहेंगे।

(4) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिशा निर्देश वर्ष 2017-18 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पूर्व, जहां आवश्यक होगा वहां पर शासन, कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0 एवं सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) आवंटित धनराशि का व्यय योजना की मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप, भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान, विभागीय परियोजना आर0के0वी0वाई0 (नोडल) अधिकारी/वित्त नियन्त्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

(8) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(9) एस0एल0एस0सी0 के अनुमोदन के विपरीत किसी अन्य कार्ययोजना/मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

(10) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी0सी0 दिनांक 29.5.2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः उक्त अवमुक्त धनराशि का भुगतान/व्यय तदनुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या 1-11011/58-2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर डी0बी0टी0 के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अतः स्वीकृत धनराशि का तदनुसार भुगतान/व्यय किया जायेगा।

(11) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का **Impact assessment** कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णतः का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाये। लाभार्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जो धनराशि उपयोग नहीं होगी, उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3 एवं कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी को प्रत्येक माह के 5 तारीख तक दो-दो प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2017-1104(1)/58-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(3) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(5) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1
(6) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0लखनऊ।
(8) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in